ई-कॉमर्स क्षेत्र भारत के लिए नया अवसर पीएलआई योजना से बढ़ेगा रोजगार : दास

रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा, इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच से ई-कॉमर्स को गति मिली

नई दिल्ली। महामारी के बाद ई-कॉमर्स क्षेत्र ने भारत के लिए नए अवसर पैदा किए हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि देश में इंटरनेट और स्मार्टफोन के विस्तार से ई-कॉमर्स क्षेत्र को मजबूती मिली और रोजगार की संभावनाएं पैदा हुईं।

एआईएमए राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन में दास ने कहा, कोविड-19 के दौरान कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्था से यह दिखा दिया कि बिना ज्यादा खर्च के भी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। देश में इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच से ई-कॉमर्स व डिजिटल बाजार को तेज रफ्तार मिली है। आगे भी इस क्षेत्र में बड़े स्तर पर रोजगार और उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था और विकास दर को गति देने के लिए विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है। मौजूदा सरकार ने इस दिशा में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के जरिये बड़ा कदम उठाया है। विनिर्माताओं को इसका लाभ उठाना चाहिए और अपनी क्षमता बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान की मूल उद्देश्य ही विनिर्माण को बढ़ावा देना है, ताकि हम आयात पर निर्भरता घटा सकें। एजेंसी

आरबीआई की गाइडलाइन...1 अक्तूबर से बदलेंगे ऑटो डेबिट नियम

नई दिल्ली। भुगतान संबंधी धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए आरबीआई 1 अक्तूबर, 2021 से ऑटो डेबिट नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इसके बाद भुगतान सेवा प्रदाता कंपनियां आपसे पूछे बिना पैसे नहीं काट सकेंगी। नए नियम के मुताबिक, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को भुगतान तारीख से 5 दिन पहले अपने ग्राहकों को एसएमएस के जरिये जानकारी देनी होगी। क्रेडिट या डेबिट कार्ड, मोबाइल एप और इंटरनेट बैंकिंग के जरिये ऑटो डेबिट करने से पहले ग्राहकों की अनुमति

लेनी होगी कि वे भुगतान करना चाहते हैं या नहीं। अगर भुगतान राशि 5,000 रुपये से ज्यादा है तो बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाएं अपने ग्राहकों को ओटीपी भेजेंगी।

इन सेवाओं पर असर... बिजली-पानी बिल, अमेजन-नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म, मोबाइल रिचार्ज, म्यूजिक एप, एपल म्यूजिक और बीमा प्रीमियम के लिए भुगतान पर।

इन सेवाओं को रखा बाहर... म्यूचुअल फंड के सिप में निवेश पर इन नियमों का असर नहीं होगा।

महामारी का गरीबों का ज्यादा असर

गवर्नर ने कहा कि दो साल से पूरी दुनिया पर छाई कोरोना महामारी की सबसे ज्यादा मार गरीबों पर पड़ी है। भारत जैसी उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश इससे बहुत प्रभावित हुए, लेकिन अब दुनिया इस दबाव से बाहर आ रही है। हमें सतत विकास हासिल करने के लिए ढांचागत निवेश और श्रम बाजार में बड़े सुधार की जरूरत है। इससे रोजगार और आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

विकास दर के लिए निजी खपत जरूरी

स्वास्थ्य और शिक्षा पर बढ़ाना होगा निवेश

दास के अनुसार, महामारी के बाद स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना होगा। साथ ही रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए डिजिटल और फिजिकल ढांचा तैयार करने पर भी जोर देना होगा। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए निजी खपत सबसे जरूरी घटक है। वित्तीय तंत्र में ढांचागत सुधारों और निवेश के जरिये नए अवसर पैदा करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए भी सरकारों को प्रयास करना होगा।